माननीय न्यायालय प्रमोद कोहली, जे.

सुरिंदर कुमार खुराना,- याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य

- उत्तरदाता

C.W.P. 1999 □□ □□□□□□ 10326

llth □□□□□□, 2008

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 14, 16 और 226 — पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग 1, अध्याय III- नियम 3.15- प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से क्लर्क के रूप में नियुक्ति- स्टेनो टाइपिस्ट के अस्थायी पद पर पदोन्नति- क्लर्क के पद पर ग्रहणाधिकार बनाए रखने का आदेश- आमंत्रित क्लर्कों के कैडर में वरिष्ठ पैमाने के लिए विकल्प- सशर्त विकल्प- विशेष रूप से किए गए क्लर्कों के कैडर में ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के लिए अनुरोध- विभाग द्वारा पदोन्नति के लिए क्लर्कों के कैडर से बाहर रखने का आदेश- न तो धारणाधिकार के अनुरोध पर विचार किया गया और न ही कैडर से पदोन्नति के लिए नाम को हटाने के आदेश को संप्रेषित किया गया- नियम 3.15 के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि किसी पद पर सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार, किसी भी परिस्थिति में, उसकी सहमति से समाप्त नहीं किया जा सकता है यदि परिणाम उसे स्थायी पद पर निहित किए बिना या निलंबित किए जाने के लिए होगा।- आज तक अस्थायी स्टेनो टाइपिस्ट का पद- याचिकाकर्ता के पास क्लर्क के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहा जो वरिष्ठ सहायक के लिए फीडर चैनल है और इस तरह की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था।.

अभिनिर्धारित किया गया कि नोट शीट (अनुलग्नक पी-9) से यह प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और दो अन्य लोगों के ग्रहणाधिकार को लिपिकों के संवर्ग में बनाए रखने का आदेश दिया, हालांकि संयुक्त पंजीयक के शपथपत्र के अनुसार, माननीय मुख्य न्यायाधीश का मूल आदेश अभिलेख की चोरी के कारण उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड है और उस समय के अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया जा सकता है। अब यह भी माना जाता है कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का एक स्थायी कर्मचारी था जिसे क्लर्क के पद पर भर्ती किया गया था। हालांकि उन्हें स्टेनो-

टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, आदेशनियुक्ति का स्वयं कहना है कि यह सेवाकालीन उम्मीदवारों से पदोन्नति है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30 नवंबर, 1991 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो आधिकारिक फाइल के नोट करने से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता के पास क्लर्क के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहा जो वरिष्ठ सहायक के लिए फ़ीडिंग चैनल है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था, जिस पर उसे विचार करने से इनकार कर दिया गया है, यह आधिकारिक उदासीनता या किसी अन्य कारण से हो सकता है।.

(□□□□ 7)

□□□□ □□ □□□□□□□, 1950 — अनुच्छेद 14, 16 □□ 226 — □□□□□□ — □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ —Steno / typist □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ — □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ — □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ — □□□□□ □□□□□□ — क्लर्कों के संवर्ग में धारणाधिकार को बनाए रखने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कोई संचार नहीं-क्लर्कों के संवर्ग से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए दावा-विभाग की अस्वीकृति-एक समान स्थिति वाले व्यक्ति को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करना-स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में काम करते हुए याचिकाकर्ता और वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं-रजिस्ट्रार जनरल को नए सिरे से विचार करने और की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आदेश देने का निर्देश दिया गया।

माना गया कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से परवीन कुमार के मामले का उल्लेख किया है, जिन्हें क्लर्क और बाद में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में भी नियुक्त किया गया था और स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में काम करते हुए, उन्हें जनवरी, 1996 में वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिका के पैराग्राफ 14 में इस संबंध में विशिष्ट कथन किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका पर एक अंतर करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि परवीन कुमार को वरिष्ठ क्लर्क के कैडर में रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता को नहीं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि परवीन कुमार ने किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। मैं अपनी चिंता को दर्ज कर सकता हूं कि उच्च न्यायालय ने किसी भी अन्य सरकारी विभाग की तरह इस मामले को लड़ा है और यहां तक कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का आदेश भी पूरी तरह से गैर-उचित है। इस तथ्य पर विवाद किए बिना कि प्रवीण कुमार वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेनो-टाइपिस्ट भी थे, एक भ्रामक अंतर बनाने की कोशिश की जाती है। वास्तव में, प्रवीण कुमार और याचिकाकर्ता के बीच कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं उच्च न्यायालय के महापंजीयक को निर्देश देता हूं कि वे मेरे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में इस आदेश को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार और उचित आदेशों के लिए रखे। चूंकि यह याचिका पिछले एक दशक से अधिक समय से लंबित है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द निर्णय लें।

(□□□□ 7)

□□.□□. □□□□, *याचिकाकर्ता* □□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□.

PERMOD KOHLI ', **□□.**

(1) चयनित होने पर, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, याचिकाकर्ता को 20 मार्च, 1989 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1991 में, स्टेनो-टाइपिस्ट के अस्थायी पदों का विज्ञापन किया गया था। चयन एक निर्धारित परीक्षा के माध्यम से किया गया था। याचिकाकर्ता को 16 जुलाई, 1991 से स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में चुना और नियुक्त किया गया था और तब से उस क्षमता में काम करना जारी है। ज्ञापन संख्या 312/स्प्ल./ईडीवीबी, दिनांक 3 दिसंबर, 1994 (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से याचिकाकर्ता से विकल्प आमंत्रित किया गया था कि क्या वह क्लर्क के मूल संवर्ग में वापस जाना चाहता है और वरिष्ठ पैमाने पर नियुक्ति को छोड़ देगा। तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था। दिनांक 12 दिसंबर, 1994 (अनुलग्नक पी-2) के अपने जवाब में याचिकाकर्ता ने क्लर्कों के वरिष्ठ पैमाने में अपनी नियुक्ति को छोड़ने का विकल्प चुना। हालाँकि, इस विकल्प के प्रयोग को सशर्त बना दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि क्लर्कों के संवर्ग में उसका ग्रहणाधिकार बरकरार रखा जाए। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे कभी सूचित नहीं किया गया था कि ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के उसके अनुरोध को कभी अस्वीकार कर दिया गया था।|

(2) दिनांक 23 सितंबर, 1997 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश के अनुसार उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को तीन अन्य के साथ वरिष्ठ क्लर्क के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह इस स्तर पर है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 नवंबर, 1997 (अनुलग्नक पी-4) को इस आधार पर वरिष्ठ सहायक के पद पर अपनी पदोन्नति की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया कि उत्तरदाता संख्या 2 और 3 क्लर्क के कैडर में उनसे जूनियर थे और उन्हें उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि चूंकि उसने क्लर्क के कैडर में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा है और इस प्रकार, वह क्लर्क के कैडर में अपनी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति का हकदार है। याचिकाकर्ता को दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 (अनुलग्नक पी-5) के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि वरिष्ठ सहायक के पद के लिए उनके नाम पर विचार करने के उनके अनुरोध पर विचार किया गया है और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने

इस अदालत से अनुरोध करते हुए वर्तमान याचिका दायर की कि वह दिनांक 23 सितंबर, 1997 (अनुलग्नक पी-3) के आदेशों को रद्द करे, जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था और साथ ही 28 अक्टूबर, 1998 (अनुलग्नक पी-5) के संचार को भी रद्द करे, जिसके द्वारा उनका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था।

(3) □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□: —

1. कि याचिकाकर्ता ने क्लर्क के कैडर में अपने ग्रहणाधिकार को बनाए रखने की शर्त के साथ क्लर्क के वरिष्ठ पैमाने में अपनी नियुक्ति को छोड़ने का विकल्प चुना था| क्लर्कों के संवर्ग में ग्रहणाधिकार को बनाए रखने की उनकी याचिका को कभी खारिज नहीं किया गया और इस प्रकार वह क्लर्कों के संवर्ग में बने हुए हैं। वह उत्तरदाताओं नं से वरिष्ठ है। 2 और 3 का अधिकार था |अपने कनिष्ठों की तुलना में वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना;

2. स्टेनो-टाइपिस्ट का पद केवल अस्थायी था और आज तक अस्थायी बना हुआ है। याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया गया है और वह भी बिना किसी वैध कारण के जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया है; और;

3. □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□-□□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□ □□ □□□ □□.

(4) जब इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी, 2008 को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए की गई कि क्या याचिकाकर्ता को ग्रहणाधिकार के प्रतिधारण के अनुरोध की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में कोई संचार दिया गया था, तो उत्तरदाताओं को रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था। स्थगित तिथि पर, न्यायालय को सूचित किया गया कि वर्ष 1997 में चोरी के

दौरान प्रासंगिक रिकॉर्ड गलत है। हालांकि, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता को कोई संचार नहीं भेजा गया था कि क्या ग्रहणाधिकार को बनाए रखने का उनका विकल्प स्वीकार किया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थियों को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (नियम) का हलफनामा 12 मार्च, 2008 को दायर किया गया था। जब मामला फिर से उठा| विचार किए जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री रैना ने 30 नवंबर, 1991 के आदेश पर भरोसा किया, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी प्रशासनिक क्षमता में पारित किया था। हालांकि, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता को कोई संचार नहीं भेजा गया था कि क्या ग्रहणाधिकार को बनाए रखने का उनका विकल्प स्वीकार किया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थियों को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (नियम) का हलफनामा 12 मार्च, 2008 को दायर किया गया था। जब मामले पर फिर से विचार किया गया, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री रैना ने 30 नवंबर, 1991 के आदेश पर भरोसा किया, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी प्रशासनिक क्षमता में पारित किया था। हालाँकि, उक्त तिथि पर प्रस्तुत रिकॉर्ड में आदेश नहीं था। तदनुसार, अभिलेख तैयार करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील, जिन्हें पहले रजिस्ट्री के आधिकारिक रिकॉर्ड से नोट्स लेने की अनुमति दी गई थी, को भी संबंधित फाइल का पता लगाने के लिए रजिस्ट्री की सहायता करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 29 मई, 2008 को एक पूरक हलफनामा दायर किया जिसमें गुम फाइल नं. V.D. 1 भाग 76क और अनुलग्नक पी-8 और पी-9 के रूप में आधिकारिक अभिलेख से टिप्पणियों के अभिलेख अंशों पर भी रखा गया। अनुलग्नक पी-8 दिनांक 17 जुलाई, 1991 का एक कार्यालय आदेश है, जिसके तहत कार्यवाहक क्लर्कों को कार्यवाहक स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में पदोन्नत करके नियुक्तियां की गई थीं, जिसमें याचिकाकर्ता उनमें से एक था। अनुलग्नक पी-9 में सरकारी नोटशीट के अंश हैं। इन नोट-पत्रकों के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि तीन व्यक्ति, अर्थात्, S.K. खुराना, राकेश खुरमी और सविता कलसी, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्हें 17 जुलाई, 1991 के आदेश (अनुलग्नक पी-8) के अनुसार स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था, को वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए नहीं माना गया था क्योंकि उन्होंने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की थी। हालांकि, इन

नोट-शीटों में यह उल्लेख किया गया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित 30 नवंबर, 1991 के आदेशों के तहत स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में नए कार्य में उनके अवशोषण तक उनके ग्रहणाधिकार को क्लर्क के कैडर में बनाए रखा गया था। 13 दिसंबर, 1994 के एक नोट में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

"तीन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को नीचे दिए गए फ़ोल्डर में देखा जा सकता है। श्री S.K. खुराना, श्री राकेश खुरमी और सुश्री सविता कलसी, स्टेनो-टाइपिस्टों ने क्लर्क के मूल कैडर में वापस नहीं लौटने का विकल्प चुना है। श्री S.K. खुराना, स्टेनो-टाइपिस्ट ने आगे अनुरोध किया है कि क्लर्क के कैडर में उनके ग्रहणाधिकार को बनाए रखा जा सकता है। यहाँ यह दोहराया गया है कि श्री S.K. खुराना, राकेश खुरमी और सविता कलसी को अस्थायी पदों के स्थान पर स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था और माननीय मुख्य न्यायाधीश दिनांक 30 नवंबर, 1991 के आदेशों द्वारा स्टेनो-टाइपिस्ट के नए कार्य में उनके अवशोषण के दौरान क्लर्क के कैडर में उनके ग्रहणाधिकार को बनाए रखने का आदेश दिया गया था। संबंधित तीन अधिकारी क्लर्क के पद पर लौटने के इच्छुक नहीं हैं। पदोन्नति के लिए उन्हें उस संवर्ग से बाहर रखा जाना है।"

(5) पूरक हलफनामे में उपरोक्त कथनों के आधार पर, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ सहायकों के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था, जो उत्तरदाता नं. 2 और 3 और उसके गैर-विचार के परिणामस्वरूप उसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। पंजाब सिविल सेवा नियम खंड के नियम 3.15 का भी संदर्भ दिया गया है। I, भाग-I, अध्याय III जो निम्नानुसार हैः —

3.15(a) इस नियम के खंड (ख) और (ग) में दिए गए उपबंध के सिवाय और नियम 3.13 के अधीन नोट में, किसी पद पर सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार किसी भी परिस्थिति में, उसकी सहमति से भी, समाप्त नहीं किया जा सकता है, यदि उसका परिणाम उसे किसी स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार या निलंबित ग्रहणाधिकार के बिना छोड़ना होगा।

(b) नियम 3.14 (ए) के प्रावधानों के बावजूद, स्थायी रूप से स्थायी पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि नियम 8.21 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद उसकी छुट्टी से इनकार कर दिया गया है; या लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के पद पर उसकी नियुक्ति पर;

(c) एक स्थायी पद पर एक सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार, उस कैडर के बाहर एक स्थायी पद (चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत हो) ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पर समाप्त हो जाएगा, जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है।"

(6) उपरोक्त नियम पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार जो स्थायी पद पर है, उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, अगर उसे स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार के बिना प्रदान किया जाता है। पहले के स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार को स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पर ही समाप्त किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि स्टेनो-टाइपिस्ट का पद अस्थायी पद था और आज तक अस्थायी बना हुआ है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता क्लर्क के कैडर में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखेगा और सेवा के पदानुक्रम में अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का हकदार है।

(7) उपर्युक्त दलीलों और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में, तत्कालीन संयुक्त पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से उच्च

न्यायालय द्वारा दायर उत्तर पर विचार किया जाना है। उच्च न्यायालय ने 28 मार्च, 1989 को एक प्रतियोगी परीक्षा और स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में उनकी आगे की नियुक्ति के माध्यम से याचिकाकर्ता के चयन और नियुक्ति को स्वीकार किया। 16 जुलाई, 1991 को यह भी स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता से विकल्प आमंत्रित किया गया था कि क्या वह क्लर्कों के वरिष्ठ पैमाने में अपनी नियुक्ति को छोड़ देता है और उसने जवाब दिया,-जवाब के माध्यम से (Annexure P-2). हालाँकि, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की क्लर्क के रूप में नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर थी। यह भी स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध भी किया था कि क्लर्क के कैडर में उसका ग्रहणाधिकार बरकरार रखा जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि क्लर्कों के संवर्ग को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात्, क्लर्क, वरिष्ठ क्लर्क और जूनियर सहायक। यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपना कैडर क्लर्क से स्टेनो-टाइपिस्ट में बदल दिया था, इसलिए वह वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय में स्टेनो-टाइपिस्ट के 17 पद विशुद्ध रूप से अस्थायी हैं और इन अस्थायी पदों को स्थायी में बदलने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता की स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में पुष्टि पर विचार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने फाइल नं. V.L.I. भाग 84. याचिकाकर्ता के पूरक हलफनामे के साथ अनुबंध पी-9 पृष्ठ 59 को मेरे सामने पेश की गई जो आधिकारिक फाइल का हिस्सा है और मूल रिकॉर्ड का सही संस्करण है। नोट-शीट (अनुलग्नक पी-9) से यह प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और दो अन्य लोगों के ग्रहणाधिकार को क्लर्क के कैडर में बनाए रखने का आदेश दिया, हालांकि संयुक्त रजिस्ट्रार के हलफनामे के अनुसार, माननीय मुख्य न्यायाधीश का मूल आदेश रिकॉर्ड की चोरी के कारण उपलब्ध नहीं है।

चूंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड है और उस समय के अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया जा सकता है। अब यह भी माना जाता है कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का एक स्थायी कर्मचारी था जिसे क्लर्क के पद पर भर्ती किया गया था। हालाँकि उन्हें स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन नियुक्ति के

क्रम में ही कहा गया है कि यह सेवा उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा है। इन परिस्थितियों में, शायद याचिकाकर्ता से विकल्प मांगा गया था-दिनांक 3 दिसंबर, 1994 (अनुलग्नक एस. पी.-1) के पत्र के माध्यम से कि क्या वह क्लर्क के पद पर वापस जाना चाहता है या वह वरिष्ठ क्लर्क के रूप में अपनी नियुक्ति को छोड़ देता है। यह भी माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित स्टेनो-टाइपिस्ट का पद विशुद्ध रूप से अस्थायी है। यह चिंता का विषय है कि उच्च न्यायालय में स्टेनो-टाइपिस्ट के 17 पद 1991 से आज तक यानि लगभग दो दशकों से खाली है, और इन पदों को संभालने वाले व्यक्तियों के पास भविष्य की कोई संभावना नहीं है, हालांकि वे लगभग 19 वर्षों से इन पदों पर काम कर रहे हैं।

सुरेंद्र कुमार खुराना बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
(Permod Kohli, J.)

चूंकि स्टेनो टाइपिस्ट का पद प्रकृति में अस्थायी है और याचिकाकर्ता को नियम 3.15 के संदर्भ में एक स्थायी पद से पदोन्नत किया गया था, इसलिए वह स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार रखता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 1991 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो आधिकारिक फाइल के नोट करने से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता के पास क्लर्क के पद पर ग्रहणाधिकार बना रहा जो वरिष्ठ सहायक के लिए फ़ीडिंग चैनल है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था, जिस पर उसे विचार करने से इनकार कर दिया गया है, यह आधिकारिक उदासीनता या किसी अन्य कारण से हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से एक प्रवीण कुमार के मामले का उल्लेख किया है जिसे क्लर्क और बाद में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में भी नियुक्त किया गया था और स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में काम करते हुए, उन्हें जनवरी, 1996 में वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। याचिका के पैराग्राफ 14 में विशिष्ट कथन किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका पर एक अंतर करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि परवीन कुमार को वरिष्ठ क्लर्क के कैडर में रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता को नहीं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि परवीन कुमार ने किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। मैं अपनी चिंता को दर्ज कर सकता हूं कि उच्च न्यायालय ने किसी भी अन्य सरकारी विभाग की तरह इस मामले को लड़ा है और यहां तक कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का आदेश भी पूरी तरह से गैर-भाषी है। इस तथ्य पर विवाद किए बिना कि प्रवीण कुमार वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेनो-टाइपिस्ट भी थे, एक भ्रामक अंतर बनाने की कोशिश की जाती है। वास्तव में, प्रवीण कुमार और याचिकाकर्ता के बीच कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 का संदर्भ दिया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के सदस्यों की नियुक्ति, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित सभी मामलों का निर्णय माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना है। इसलिए एक आदेश जारी करने के बजाय, मैं उच्च न्यायालय के महापंजीयक को निर्देश देता हूं कि वे इस आदेश को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके लॉर्डशिप के विचार और उचित आदेशों के लिए, मेरे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में रखें। चूंकि यह याचिका पिछले एक दशक से

अधिक समय से लंबित है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द निर्णय लें|

(8) उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निपटारा किया जाता है|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा